

संस्करण : ग्वालियर

वर्ष : 03

अंक : 77

पृष्ठ : 6

मूल्य : 2.00

शुक्रवार,17 अक्टूबर 2025

ग्वालियर, मुम्बई, लखनऊ एवं प्रयागराज ,से एक साथ प्रकाशित एवं गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ से प्रसारित

3 शिव शांति आश्रम पहुंचे सीएम योगी, संत शिरोमणि

4 महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के बाद बिहार- राहुल

5 जीवन अनिश्चित लगने पर 'योग' की ओर लौटीं



आंध्र प्रदेश के श्रीसैलम में पहुंचे पीएम मोदी

मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में की पूजा-अर्चना



श्रीशैलम (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को यहां नांदयाल जिले में श्री भ्रामरामम्बा

मल्लिकार्जुन स्वामी वारला देवस्थानम में पूजा-अर्चना की। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के

सूत्रों ने बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने पंचमुखु (पाच के दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बना एक पवित्र मिश्रण)

से रुद्राभिषेक किया। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण भी उनके साथ थे। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 52 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर की एक अनूठी विशेषता यह है कि एक ही परिसर में एक ज्योतिर्लिंग और एक शक्तिपीठ है। यह पूरे देश में इस तरह का पहला मंदिर है। मंदिर दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी श्री शिवाजी स्मूर्ति केंद्र गए, जो एक स्मारक परिसर है। इसमें एक ध्यान कक्ष भी है जिसके चारों कोनों पर चार प्रतिष्ठित किलों, प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी के मॉडल स्थापित हैं। बीच में महान राजा छत्रपति शिवाजी की गहन ध्याना मुद्रा में एक प्रतीका स्थापित

है। श्री शिवाजी स्मारक समिति द्वारा संचालित इस ध्यान कक्ष की स्थापना 1677 में छत्रपति शिवाजी की पवित्र तीर्थस्थल की ऐतिहासिक यात्रा की स्मृति में की गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री कुरुनूल जाएंगे और वहां बिजली, रक्षा, रेलवे और पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री सुपर जीएसटी-सुपर सेविंग्स नामक एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें लोगों को नई पीढ़ी के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों के लाभों के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले, कुरुनूल हवाई अड्डे पर राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री नायडू और अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया।

सीएम धामी ने पशुपतिनाथ मंदिर में चढ़ाई घंटी



उधमसिंहनगर (एजेंसी)। सीएम

पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को खटीमा स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को खटीमा स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धा और आस्था के प्रतीक के रूप में मंदिर में बड़ी घंटी चढ़ाई सीएम ने मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मंदिर परिसर में उपस्थित महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने फूल-मालाओं और जयकारों के साथ सीएम का अभिनंदन किया। पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह से सराबोर हो गया। पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक धरोहर ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा

कि हमारा राज्य देवभूमि है। यहां के हर मंदिर और हर धाम में लोक आस्था बसती है। इन पवित्र स्थलों के संरक्षण और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है। इससे पूर्व सीएम ने झनक्ड़वां के वन शक्ति मंदिर में रुककर दर्शन किये। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दजामंत्री फरजाना बेगम, अनिल कपूर डब्यू, शंकर कोरंगा, पूर्व विधायक डॉ प्रेम सिंह राणा, मोहनी पोखरिया, किशन सिंह (किना), जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण जय किशन, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, मुख्य चिकित्साधिकारी के के अग्रवाल, मंदिर समिति के अध्यक्ष जेपी सिंह, संरक्षक बृज बिहारी, उपाध्यक्ष चंद्र कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष पी एन सक्सेना, सचिव सुशील सक्सेना आदि मौजूद थे।

सम्राट चौधरी ने किया नामांकन, कहा एनडीए शासन में बिहार विकास के मार्ग पर अग्रसर

पटना (एजेंसी)। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बृहस्पतिवार को मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया और कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार में राज्य समृद्धि और विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वर्तमान में विधान परिषद सदस्य चौधरी 15 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में चौधरी ने कहा, लोगों ने राजग शासन में हुए विकास कार्यों को देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हर क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और राजग शासन ने बिहार को समृद्धि और तौर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है।

वोट चोरी में भाजपा की सल्लसता, ईसी मौन: दिविवजय सिंह

बाराबंकी (एजेंसी)। देश में वोट चोरी का मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यह आरोप मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिविवजय सिंह ने लगाया। बाराबंकी में दिविवजय सिंह एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। दिविवजय सिंह ने कहा कि भाजपा की इस वोट चोरी में पूरी सल्लसता है, जबकि चुनाव आयोग मूकदर्शक बना हुआ है। उन्होंने खुलासा किया कि साल 2003 से बिहार की मतदाता सूची से 62 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा चुके हैं, जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि उनकी नागरिकता और भविष्य क्या होगा। उन्होंने कहा, वे लोग कहां रहेंगे, किस देश के नागरिक माने जाएंगे। इस पर कोई जवाब नहीं है। यह देश के लिए अत्यंत दुखद स्थिति है। बिहार चुनाव पर पूछे गए सवाल पर सिंह ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। जीतने का इमेज प्राप्त होने के बाद पटना सिविल कोर्ट के प्रभावी निबंधक ने तत्काल पुलिस को सूचित किया एवं जिला अधिवक्ता संघ के सचिव को सूचना देते हुए सुरक्षाार्थ सिविल कोर्ट परिसर खाली करने का अनुरोध किया। इसके बाद सभी न्यायिक पदाधिकारी ,कर्मचारी एवं आमजनो को भी सिविल कोर्ट परिसर से धीरे-धीरे बाहर निकाला गया तथा किसी भी व्यक्ति का प्रवेश परिसर में बंद कर दिया गया। प्रशासन ने भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल न बने, इसका ख्याल रखा और शांतिपूर्वक परिसर को खाली कराया। कीलों ने भी अपने बैठने की सभी जगह खाली कर दी और सिविल कोर्ट परिसर से बाहर चले गए। परिसर खाली होने के बाद अदालती कामकाज पूरी तरह से बंद हो गया। इस बीच पटना पुलिस का बमनिरोधक दस्ता, श्वान दस्ता एवं वरीय पदाधिकारी तत्काल सिविल कोर्ट पहुंचे और चप्पे-चप्पे की तलाशी लेनी शुरू कर दी।

बिहार चुनाव: जदयू की दूसरी लिस्ट जारी , 44 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की

पटना (एजेंसी)। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में शामिल जदयू ने गुरुवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इस सूची में कुल 44 उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे पहले बुधवार को पार्टी ने 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। सूची के मुताबिक, रुपौली से कलाधार मंडल को प्रत्याशी बनाया गया है जबकि धमदाहा से मंत्री लेसी सिंह फिर से चुनावी मैदान में होंगी। इसी तरह शीला मंडल फुलपरास से, जबकि कदवा से दुलालचंद गोस्वामी, बरारी से विजय सिंह निषाद, गोपालपुर से बुलुो मंडल, सुल्तानगंज से ललित नारायण मंडल और चकाई से मंत्री सुमित कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। झांझा से दामोदर रावत, नवादा से विभा देवी, बेलागंज से मनोरमा देवी,

रफीगंज से प्रमोद कुमार सिंह और नबीनगर से पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद को टिकट दिया



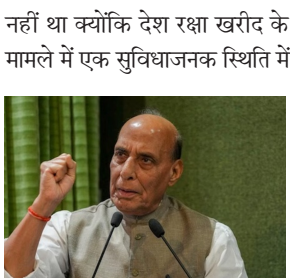
गया है। इसके अलावा घोसी से ऋतुराज कुमार जदयू के प्रत्याशी होंगे। जहानाबाद से पार्टी ने चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, कुर्था से पप्पू कुमार वर्मा, नोखा से नागेंद्र चंद्रवंशी और चौनपुर से मंत्री जमा खान को उम्मीदवार बनाया है। काराकाट से महाबली सिंह एनडीए के प्रत्याशी होंगे तो

कहलगांव से शुभानंद मुकेश चुनावी मैदान में उतरेंगे। उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने रविवार को सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी। इस बंटवारे के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 101-101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को 29 सीट मिली हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीवन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और राज्यसभा सदस्य उषेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को छह-छह सीटें मिली हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी।

ऑपरेशन सिंदूर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण: राजनाथ सिंह

पुणे (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को ऑपरेशन सिंदूर को भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए कहा कि इस मिशन के दौरान सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल किए गए अधिकतर उपकरण स्वदेशी थे। सिंह ने कहा कि भारत ने अब उस बाधा को तोड़ दिया है जो आजादी के बाद से बनी हुई थी और सरकार ने देश के भीतर हथियारों के निर्माण को जोर शोर से बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2029 तक घरेलू रक्षा विनिर्माण को तीन लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना और रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये तक

पहुंचाना है। केन्द्रीय मंत्री ने पुणे में सिम्बायोसिस रिकल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, हमने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। शुरूआती दौर में यह मुश्किल था क्योंकि हम पूरी व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे थे। आजादी के बाद से हम हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। हमारे लिए विदेशों से रक्षा उपकरण खरीदना एक जरूरत बन गई थी और स्वदेशी उत्पादन लगभग न के बराबर था। मंत्री ने कहा कि भारत ने अब उस बाधा को तोड़ दिया है जो आजादी के बाद से बनी हुई थी। उन्होंने कहा, हमने देश में ही हथियारों के निर्माण को जोर शोर से बढ़ावा दिया है। यह बिल्कुल भी आसान



पहुंच गया था। हम दूसरे देशों से हथियार खरीदने के आदी हो गए थे। सिंह ने कहा कि न तो घरेलू स्तर पर हथियारों का उत्पादन करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति थी और न ही रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कोई कानूनी ढांचा था। रक्षा मंत्री ने बताया कि देश के युवाओं में इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने की

प्रेरणा का भी अभाव था। उन्होंने कहा, स्थिति हमारे लिए अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल थी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी हम रुके नहीं। हमने रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव कदम उठाए और आज उन प्रयासों के स्पष्ट परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा, आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी देखी होगी। ऑपरेशन सिंदूर भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है क्योंकि सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल किए गए अधिकतर उपकरण स्वदेशी थे। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने इस वर्ष में निर्यंत्रण रेखा के पार और पाकिस्तान के भीतर आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, दिवाली से पहले ही गाजियाबाद- नोएडा का बुरा हाल

नोएडा (एजेंसी)। दिल्ली-एनसीआर में दिवाली से पहले ही वायु प्रदूषण ने खतरनाक स्तर पार कर लिया है। गुरुवार सुबह आंकड़ों से पता चलता है कि गाजियाबाद के लोनी और नोएडा के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता दिल्ली के अधिकार क्षेत्रों से भी अधिक खराब स्थिति में पहुंच गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 के पार, यानी शबहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। गाजियाबाद में लोनी का



के सेक्टर-125 में एक्यूआई 358 तक पहुंचा, जो चिंता का सबसे बड़ा कारण है। गाजियाबाद के अन्य इलाके भी पीछे नहीं हैं- वसुंधरा और इंदिरापुरम दोनों का एक्यूआई 287 है और संजय

नगर का एक्यूआई 260 रहा। नोएडा में हालात गंभीर बने हुए हैं। सेक्टर-116 में एक्यूआई 334, सेक्टर-1 में 257 और सेक्टर-62 में 207 दर्ज किया गया। दिल्ली में भी स्थिति बेहतर नहीं है। आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार का एक्यूआई 335, वजीरपुर का 337, बवाना का 281 और मुंडका का 297 है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन अधिकार इलाके खराब से बहुत खराब श्रेणी में हैं।

बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, दोनों पक्षों में जबरदस्त बहस

नई दिल्ली (एजेंसी)। बिहार चुनाव को लेकर हुए वोटर लिस्ट संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सुर्वकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह सुनवाई की। अदालत में एडीआर यानी याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने जोरदार अपील की। उन्होंने चुनाव आयोग को फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़े और हटाए गए नामों की सूची जारी करने का निर्देश देने को कहा। उधर आयोग ने लिस्ट, प्रकाशित

करने की प्रक्रिया में होने की बात कही। इसके बाद बेंच ने कहा कि वो देखेंगे कि आयोग क्या प्रकाशित करता है। जस्टिस कांत ने कहा-हमें कोई संदेह नहीं कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे...वे वोटर लिस्ट प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं... हमारी इस पर नजर है... हम मामला बंद नहीं कर रहे हैं। वहीं वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को हटाए गए और जोड़े गए नामों को कारण सहित तत्काल प्रकाशित करना चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील



अंतिम सूची प्रकाशित करने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए 17 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है, इसलिए रोल उस तारीख तक फ्रीज हो

जाएंगे। जिसपर जस्टिस कांत ने चुनाव आयोग से कहा कि घेखते हैं कि आप क्या प्रकाशित करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में इन चीजों को देखेंगे और उपचारात्मक उपाय लेकर आएं। आयोग ने ये भी बताया कि हटाए गए नामों के खिलाफ कोई अपील नहीं मिली है, जबकि कोर्ट ने पिछले हफ्ते मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित की थी. अब इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख दे दी है।

सपा के चरित्र में राजनीतिक ईमानदारी का साहस नहीं

लखनऊ (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से नजदीकियां बढ़ाने के समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोप का जवाब देते हुये बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रियो मायावती ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी ने स्मारकों के रखरखाव पर टिकटों से प्राप्त धनराशि खर्च किये जाने पर मौजूदा सरकार का आभार प्रकट किया जिसका विरोधियों को पसंद नहीं आना लाजिमी है क्योंकि उनके स्वाभाव और चरित्र में राजनीतिक

ईमानदारी का साहस नहीं है। पार्टी की प्रदेश इकाई की विशेष बैठक को संबोधित करते हुये उन्होंने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी कैडों को पूरे तन, मन, धन के साथ लग जाने की अपील की और पार्टी संगठन के गठन को लेकर शेष बचे कार्यों को अविलम्ब पूरा करने के निर्देश दिये। बैठक में उत्तराखण्ड स्टेट के पार्टी पदाधिकारी भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में उपेक्षित रहे बसपा सरकार द्वारा लखनऊ में निर्मित भव्य स्थल, स्मारक, पार्क से टिकट की बिक्री से प्राप्त



वर्तमान सरकार का आभार प्रकट करने की बसपा की राजनीतिक ईमानदारी भी विरोधियों को अच्छा नहीं लगना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके चरित्र में

स्वस्थ राजनीतिक ईमानदारी का साहस नहीं है। बसपा अध्यक्ष ने सपा अध्यक्ष के एक अन्य आरोप का भी जवाब देते हुये कहा कि नो अक्टूबर को कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर महा-आयोजन में पार्टी के लोग प्राइवेट बसों व ट्रेजों पर अपना खर्च करके तथा अपने खुद के छोटे-मोटे साधनों से व पैदल भी चलकर आये थे तो फिर सरकार बसें बीच में कहां से आ गई है, जिनका कुछ विरोधी लोग खिसियानी बिल्ली खम्बा नौचे की तरह, अनाप-सनाप व बेकुरी बाँव कर रहे हैं।

डरे हुए प्रधानमंत्री... ट्रंप के दावे को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, वे घोषणा करते और ये सराहना संदेश भेजते

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक नए दावे को लेकर बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, ट्रंप से डरे हुए हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, वह (मोदी) भ्रेमिष्ठ हैं। हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। भ्रेमिष्ठ ने मुझे आश्वासन दिया है कि रूस से कोई तेल खरीद नहीं



को यह निर्णय लेने दिया और घोषणा करने दी कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी बार-बार आलोचना

के बावजूद ट्रंप को सराहना वाले संदेश भेजते रहते हैं। राहुल गांधी ने कहा, वित्त मंत्री का अमेरिका दौरा रद्द हो गया। शर्म अल-शेख (गाजा शांति प्रस्ताव से संबंधित शिखर सम्मेलन) में भाग नहीं लिया गया। ऑपरेशन सिन्दूर पर ट्रंप के दवा का खंडन नहीं किया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख निर्णयों को अमेरिका को आउटसोर्स कर दिया है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के 65 रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं से जुड़े प्रमुख विभिन्न कार्यों का राष्ट्र को समर्पण किया



नई दिल्ली,: रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने आज खातीपुरा रेलवे स्टेशन का दौरा किया और राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने तथा आधुनिक और कुशल रेल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरूआत की। ये पहल राज्य के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर

को रूपांतरित करने और यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम हैं। अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के 65 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इनमें रामसर, सिवानी, लूनी, पृथ्वीराज पुर और भगत की कोठी जैसे स्टेशन

शामिल हैं। इन सुधारों में प्रतीक्षालयों का आधुनिकीकरण, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, उन्नत स्वच्छता सुविधाएँ, बैठने की सुविधाएँ, स्पष्ट साइनबोर्ड और दिव्यांगजन के अनुकूल इंतजाम शामिल हैं, जिससे स्टेशन और अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और यात्रियों के अनुकूल बन गए हैं। साथ ही, केंद्रीय मंत्री ने जयपुरझाआसारवा एक्सप्रेस की सभी एसी श्रेणियों में

मुद्रित कंबल कवर (स्रश्र्ल्लशी ुल्लिश्रू,इध्र्श्र२) की नई व्यवस्था शुरू की, जिससे यात्रा में स्वच्छता, एकरूपता और आरामदायक अनुभव सुनिश्चित होगा। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे का विकास कई मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई प्रकर की ट्रेनों की शुरूआत, नए स्टेशनों का निर्माण, नई रेल लाइनें, विद्युतीकरण कार्यों की पूर्णता और आधुनिक

खरखवा डिपो का निर्माण जारी है। उन्होंने कहा कि इन सबके साथ ही रेलवे का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के जीवन में सार्थक बदलाव लाना है। केंद्रीय बजट 2025 26 में राजस्थान में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 9,960 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो तेजी से विस्तार और आधुनिकीकरण को आगे बढ़ा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत

प्रदेश में 85 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें से इस वर्ष 8 स्टेशनों का लोकार्पण हो चुका है। राज्य में आज 12 वंदे भारत सेवाएं संचालित हो रही हैं, जो प्रमुख मार्गों पर तेज, सुनिश्चित और आरामदायक यात्रा प्रदान कर रही हैं। ये योजनाएँ राजस्थान में आधुनिक, कुशल और यात्री-केंद्रित बुनियादी ढांचे के निर्माण के प्रति रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

पिछड़े वर्ग के 5 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे सीएम योगी

छात्रवृत्ति वितरण के द्वितीय चरण में 4.83 लाख से अधिक छात्रों को वितरित करेंगे 126.68 करोड़ रुपये की धनराशि
पहले चरण में 2.5 लाख से अधिक ओबीसी छात्रों को लगभग 62.13 करोड़ रुपये की धनराशि से किया जा चुका है लाभान्वित
पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए अब तक 188 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति होगी वितरित, डीबीटी से बढ़ी पारदर्शिता
योगी सरकार ने छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति बजट में रिकॉर्ड वृद्धि करते हुए 2025-26 में 3124 करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था की

लखनऊ,: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लोक भवन स्थित ऑडिटोरियम में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के लाखों युवाओं के खाते में सीधे छात्रवृत्ति ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2025-26 से सितंबर माह में ही

छात्रवृत्ति वितरण का प्रारंभ किया है। पहले चरण में लगभग 62.13 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय कर 2.5 लाख से अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को लाभान्वित किया जा चुका है। वहीं, द्वितीय चरण में शुक्रवार को 126.68 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय कर 4.83 लाख से अधिक छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि जब प्रदेश का युवा शिक्षित होगा तभी विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश के द्घाशताब्दी संकल्प-2047हू का साकार किया जा सके गा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वंचित एवं कमजोर आय वर्ग के छात्रों के शैक्षिक उन्नयन हे तु छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की

प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और पूर्णतः डिजिटल बनाया है। इसी के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली बार सितंबर माह से ही छात्रवृत्ति वितरण प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट 1295 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3124.45 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी यह 2.5 गुना से अधिक वृद्धि है। केवल छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के बजट में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2016-17 में यह 1092.36 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 2825 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति का वितरण अब पूरी तरह ऑनलाइन व डीबीटी के माध्यम से आधार-संलग्न बैंक खातों में किया जा रहा है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और त्वरिता दोनों बढ़ी हैं। सरकार की इन पहलों का उद्देश्य हर वर्ग के युवा को आत्मनिर्भर बनाना और शिक्षा के माध्यम से समाज में समान अवसर

सुनिश्चित करना है। विभागीय योजनाओं के बजट में वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2025-26 में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना का बजट 107.33 रुपये करोड़ से बढ़ाकर 325 रुपये करोड़ किया गया है, जबकि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए आवंटन 984.62 रुपये करोड़ से बढ़ाकर 2500 रुपये करोड़ कर दिया गया है। इसी प्रकार, शादी अनुदान योजना का बजट 141.55 रुपये करोड़ से बढ़ाकर 200 रुपये करोड़, तथा कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना का बजट 11 रुपये करोड़ से बढ़ाकर 35 रुपये करोड़ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, छात्रावास अनुरक्षण हेतु 5 रुपये करोड़ तथा योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए 1 रुपये करोड़ का प्रावधान पहली बार किया गया है। इन बजटीय बढ़ोतरी से यह स्पष्ट है कि सरकार ने विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं व्यापक लाभार्थी वर्ग तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ठोस वित्तीय प्रतिबद्धता दिखाई है।

पत्नी का हत्यारोपी पति पेड़ से लटका मिला, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप

कानपुर। शुक्लागंज के लालता खेड़ा में बुधवार को पत्नी की हथौड़ी मारकर हत्या करने वाला आरोपी पति गुरुवार सुबह पेड़ से लटका

में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं, शव उतारने के दौरान मृतक के परिजनों ने हंगामा किया और आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने

व परिजन की वहां पहुंच गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सुशील ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके देवर को उसकी ससुराल वालों ने



मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। शुक्लागंज में गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के लालता खेड़ा गांव में पत्नी के हत्यारोपी पति का शव उसके घर से चार सौ मीटर की दूरी पर स्थित एक आम के बाग में लगे चिलबिल के पेड़ से फंदे के सहारे लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे

मारकर उसे लटका दिया है। गुरुवार की सुबह करीब 11:30 बजे ललिता खेड़ा गांव के रहने वाले राजेश लोधी (32) पुत्र कमलेश का शव उसके घर से करीब 400 मीटर की दूरी पर स्थित क्षेत्र के रहने वाले कैलाश द्विवेदी के आम के बाद में लगे चिलबिल के पेड़ से मटक देखा गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इस दरमियान मृतक राजेश की भाभी सुशीला देवी

सीमा की उसके पति राजेश लोधी ने सिर पर हथौड़ी से ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी थी। मृतका के पिता रामकुमार की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास, ससुर सहित छह के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। सास और ससुर को हिरासत में लेकर पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही थी। इसका आज सुबह शव फंदे से लटका मिला।

संक्षिप्त खबरें

दीपावली मेला का हुआ आयोजन

हरैया। बुधवार को कस्बे के एक निजी स्कूल में दीपावली मेले का आयोजन हुआ। शुभारंभ उप जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह ने किया। मेले में छात्रों ने खाद्य स्टॉल, विज्ञान, कला एवं सामाजिक अध्ययन की प्रदर्शनी के जरिए प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम मेले का मुख्य आकर्षण रहे। विद्यार्थियों ने ऑपरेशन सिंदूर, न्यू पार्लियमेंट, ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषयों पर मॉडल प्रदर्शित किए। छोटे बच्चों ने राम, सीता, रावण अहिल्याबाई और झांसी की रानी के चित्रण से सबका मन मोहा। नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने छात्रों का हौसला बढ़ाया। विजेताओं को नीलम शुक्ला ने पुरस्कृत किया। कविता त्रिपाठी, वर्तिका त्रिपाठी, करुणेश मणि पाठक आदि मौजूद रहे।

प्रदेश गन्ना समिति संघ के अध्यक्ष बने सिद्धांत

हरैया। विक्रमजोत गन्ना समिति के अध्यक्ष सिद्धांत सिंह प्रदेश गन्ना समिति संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। मंगलवार को लखनऊ में समितियों के अध्यक्षों की हुई बैठक में सिद्धांत को सर्व सम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत होने पर समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अरविंद सिंह, राजेश पांडेय, मंजू सिंह आदि ने बधाई दी।

जमीन के झांसे में 10 लाख हड़पने का आरोप

बस्ती। शहर के निकट जमीन लेने के बहाने लोगों से लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता गौरव कुमार श्रीवास्तव ने कोतवाली पुलिस को बताया कि मड़वानगर बीटेक चाय वाले की गली निवासी श्यामसुंदर गुप्ता और उनकी पत्नी संध्या कसौधन ने जमीन का बड़ा व्यवसायी होने का झांसा देकर करीब 10 लाख रुपये एग्रीमेंट और नकद व चेक के माध्यम से ले लिया लेकिन रजिस्ट्री कराने से इन्कार कर दिया। शिकायत में कहा गया कि श्यामसुंदर ने खुद को शहर के पास कई जमीनों का कारोबारी बताया और एडवांस देने पर 10 प्रतिशत कम करके रजिस्ट्री कराने का वादा किया। श्यामसुंदर के घर जाकर उनकी पत्नी से मिलने पर भी उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया। शिकायतकर्ता ने समय-समय पर रकम दी, लेकिन जून 2025 तक रजिस्ट्री कराने का वचन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब रकम लौटाने के लिए कहा तो आरोपियों ने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। झूठे मुकदमों में फंसाने की भी बात कही। कोतवाल दिनेश चंद्र चौधरी ने बताया कि तीन आरोपियों पर केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।

भव्य रामलीला जन जागरण शोभायात्रा 26 को

बस्ती। सनातन धर्म संस्था की ओर से महिला महाविद्यालय में 26 अक्तूबर को आयोजित श्री रामलीला महोत्सव और भव्य जन जागरण शोभायात्रा की तैयारी बैठक की गई। दीप प्रज्ज्वलन एवं श्री राम स्तुति से शुभारंभ किया गया। श्याम जी चौधरी ने बताया कि जन-जन में रामत्व स्थापित करने के लिए संस्था प्रयासरत है। पंडित गोपेश्वर त्रिपाठी ने पिछले वर्षों में रामलीला की ओर से नौनिहालों में संस्कार देने के प्रयासों की सराहना की। डॉ. शैलेश सिंह ने बच्चों को श्री रामजी के जीवन से जोड़कर रामत्व स्थापित करने पर जोर दिया। कात्यायनी दुवे ने कहा कि बढ़ते अपराध, धर्म की हानि और बच्चों का माता-पिता से विमुख होना जैसी समस्याओं को श्री रामलीला महोत्सव के माध्यम से कम किया जा रहा है। डॉ. आशीष नारायण त्रिपाठी ने शोभा यात्रा को अविस्मरणीय बनाने का आवाहन किया। कर्नल केसी मिश्र और महिला महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. सुनीता तिवारी ने बच्चों को श्री राम जी से प्रेरणा लेकर राष्ट्र और धर्म के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। मनीष सिंह ने बताया कि 26 अक्टूबर को सुबह 10 बजे श्री कृष्ण कुमार पांडेय इंटर कॉलेज स्टेशन रोड से रोडवेज, गांधीनगर, कंपनी बाग होते शिव मंदिर अमहट घाट तक जन जागरण शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। पंकज त्रिपाठी, अनुराग शुक्ल ने बताया कि सभी समाजजन से सपरिवार पीत वस्त्रों में शामिल होने का आह्वान किया गया है। नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुर वर्मा ने कहा कि यह महोत्सव बस्ती का प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम बन चुका है, और नगर पालिका द्वारा सफाई, पेयजल, मोबाइल शौचालय एवं फॉगिंग जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

सिंचाई कर्मियों ने प्रमुख अभियंता को सौंपा ज्ञापन

बस्ती। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बुधवार को मिनिस्टीरियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट के मंत्री राजेश कुमार वरुण और अशोक कुमार सिंह की अगुवाई में प्रमुख अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन, परियोजना एवं नियोजन को ज्ञापन सौंपा। समस्याओं के प्रभावी और शीघ्र समाधान की मांग की। ज्ञापन में पुरानी पेंशन बहाली, नुटिपूर्ण वरिष्ठता सूची जारी करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट लागू करने, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक एवं प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पदों पर अविलंब प्रोन्नति की मांग की गई। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के पदों का 50:30:20 के अनुपात में विभाजन, लिपिकीय सर्वग (कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक) के कार्य एवं दायित्व का निर्धारण, अधिष्ठान-4क अनुभाग में कार्यरत मुकुल कुमार को हटाने और उनके कार्यों की जांच कराने आदि मांगें की गईं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री तौलू प्रसाद ने मांगों को शीघ्र पूरा कराने पर जोर दिया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार पांडेय, तुलसीराम, श्रीकांत, दीपक सिंह, राहुल श्रीवास्तव, इन्द्रजीत, अनिल कुमार, राधेश्याम, रंजीत वर्मा, सुजीत कुमार, श्रवण, अजीत कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन पर कचहरी में शोक

बस्ती। वरिष्ठ अधिवक्ता युगल किशोर पांडेय के असामयिक निधन पर न्यायालय और बार एसोसिएशन में गहरा शोक छा गया। बुधवार को जिला जज विनय कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं की उपस्थिति में न्यायालय के सभागार में शोक सभा आयोजित की गई। उपस्थित सभी ने मृत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर प्रार्थना की। शोक सभा में न्यायिक अधिकारी प्रमोद कुमार गिरि, कमलेश कुमार, विनोद कुमार सप्तम, रामकरण, आशीष कुमार राय, पीयूष कुमार, सत्यभामा कोशिकी, अभय देवेश शुक्ला, चौधरी संदीप सिंह, अभिशेष जायसवाल, सोनाली मिश्र, राजा बाबू, एसीजेएम प्रथम और द्वितीय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अधिवक्ताओं में चंद्रभूषण मणि त्रिपाठी, विचित्र मणि, बोरेंद्र यादव, अजय सिंह, मारूत कुमार शुक्ला, रविशंकर शुक्ला तथा अन्य शामिल थे।

सड़क किनारे बोरे में मिला कुत्ते का शव

दुबौलिया। थाना क्षेत्र के राम जानकी मार्ग पर रवावपुर राजा गांव के पास सड़क किनारे बोरे से दुर्गंध फैलने लगी। राहगीरों ने डायल 112 और दुबौलिया पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष केके साहू ने बोरे को खुलवाया तो उसमें कुत्ते का शव मिलने की जानकारी मिली। हालांकि पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद स्पष्ट किया कि यह मानव नहीं, बल्कि कुत्ते का शव है।

संक्षिप्त समाचार

पॉक्सो एक्ट के बारे में दी जानकारी
ग्वालियर। समेकित बाल संरक्षण मिशन वात्सल्य योजना के तहत बुधवार को शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय में पॉक्सो एवं जे.जे.एक्ट विषय पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में बाल संरक्षण अधिकारी ज्योति गर्ग एवं हार्टबीट फाउंडेशन से आलोक बेंजामिन ने पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार के अपने बचाव के लिए एक्ट के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। संस्था प्रमुख संभागीय आयुक्त संजय खेडकर द्वारा बच्चों को भयमुक्त वातावरण में रहने की आवश्यकता की बात कही। संचालन दिनेश भट्टारिया एवं आभार तपन ओझा ने व्यक्त किया।

आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय का नाम बदला
ग्वालियर। राज्य शासन ने आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय का नाम बदलकर अब कार्यालय आयुक्त, भू-संसाधन प्रबंधन कर दिया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना 26 अगस्त को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई है। नए नाम के प्रभावी होने के साथ ही सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आगे से कार्यालय आयुक्त, भू-संसाधन प्रबंधन के नाम से ही पत्राचार करें। साथ ही कार्यालय की पद-मुद्रा (सील/स्टांप) पर भी नया नाम अंकित किया जाएगा। इस संशोधन के बाद राज्य में भू-अभिलेख से संबंधित समस्त शासकीय कार्यवाही अब भू-संसाधन प्रबंधन शीर्षक के अंतर्गत होगी।

समस्याओं के निराकरण के लिए बैठक कल
ग्वालियर। समाधान ऑनलाइन में चर्चनित विषयों से संबंधित समस्याओं का तेजी से निराकरण करने के निर्देश संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। इसको लेकर 17 अक्टूबर को संभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक प्रातः 11.15 बजे संगणक आयुक्त कार्यालय के सभागार में रखी गई है।

ऊर्जा मंत्री आज करेंगे सड़क मार्ग का लोकार्पण
ग्वालियर। उप नगर ग्वालियर में जुड़ रहे विकास कार्यों की श्रृंखला में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गुरुवार 16 अक्टूबर को सुबह 10 सेवानगर से रमटापुरा की पुलिया तक पवन निर्मित सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। यह लोकार्पण कार्यक्रम रमटापुरा में दीना कुशवाह के निवास के निकट आयोजित होगा।

मेले में वाहनों के विक्रय पर रोड टैक्स में छूट के लिए संभागीय आयुक्त ने शासन को लिखा पत्र

ग्वालियर
ग्वालियर व्यापार मेले का आयोजन 25 दिसंबर से होने जा रहा है। वाहन खरीदारों के लिए खुश खबरी यह है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार भी उन्हें रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिल सकती है। इस छूट का लाभ प्रदेश भर के लोग उठाते हैं। इस संबंध में संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने शासन को पत्र लिखा है।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष वाहनों पर रोड टैक्स में छूट मिलने पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2630 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। जिसमें 27 हजार से अधिक वाहनों की बिक्री हुई थी जिसमें 13657 चार पहिया और 13122 दो पहिया वाहन बिके थे। साथ ही

सराफा बाजार में स्टैंडर्ड सोना और पक्की चांदी की बड़ी मांग

पुष्य नक्षत्र पर चमक उठा बाजार, रात तक हुई खरीदारी

ग्वालियर
पुष्य नक्षत्र के दूसरे दिन बुधवार को शहर के बाजार चमक उठे। सुबह से शुरू हुई खरीदारी रात तक जारी रही। सराफा कारोबारियों के अनुसार सोना-चांदी के बढ़े दामों के कारण लोगों की दिलचस्पी स्टैंडर्ड सोना और पक्की चांदी में बढ़ गई है और लगे इसे खरीदने के लिए स्वर्ण कारोबारियों के पास पहुंचकर बुकिंग करा रहे हैं। कारोबारियों के अनुसार लोग इस धातु को निवेश की वस्तु मान रहे हैं। वहीं जेवरात में लोगों की दिलचस्पी कम हो गई



है। इन्हें आवश्यकता के अनुसार खरीदा जा रहा है। स्थानीय सराफा बाजार में बुधवार को 24 कैरेट का स्टैण्डर्ड सोना 1 लाख 32 हजार रुपए का 10 ग्राम और पक्की चांदी 1 लाख 82 हजार रुपए

किलो बिकी है। चांदी का सिक्का भी 2000 रुपए पर पहुंच गया है। दीपावली पर लक्ष्मी आगमन से पहले घर और बाजार सजकर तैयार हो गए हैं। ऐसे में पुष्य नक्षत्र पड़ने पर लगभग सेक्टरों में

शहर की सड़कों पर न दिखे कचरा समय पर निकलें सभी वाहन

अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव ने की स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा

ग्वालियर
दीपावली के पर्व को देखते हुए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी क्षेत्र में लगातार भ्रमण करें एवं प्रत्येक क्षेत्र में समय पर वाहन पहुंचते तथा सभी वाहन अतिरिक्त चक्कर लगाएँ जिससे किसी भी क्षेत्र में सड़क पर कचरा न दिखे। इसके साथ ही अतिरिक्त वाहन लगाने की आवश्यकता हो तो वह भी लगा लें। साथ ही दीपावली के दिन भी सभी कर्मचारी दोपहर एक बजे तक सफाई व्यवस्था में कार्य करें। यह निर्देश अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव ने स्वच्छता की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में अपर आयुक्त ने निर्देश दिए कि किसी भी सड़क पर कचरा न दिखे, डोर टू डोर वाहन समय



पर निर्धारित मार्ग पर पहुंचे। कार्यशाला प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि डिपो से सभी वाहन समय पर निकलें। इसके साथ ही सेकेंडरी वाहन भी अतिरिक्त चक्कर लगाकर कचरे को निर्धारित कचरा स्टेशन पर पहुंचाएं। इसके साथ ही कार्यशाला प्रभारी को निर्देश दिए गए कि अतिरिक्त वाहन लगाने की आवश्यकता हो तो जेडएचओ एवं स्वास्थ्य अधिकारी की डिमांड पर उन्हें वाहन उपलब्ध कराएं। बैठक में रात्रि कालीन सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दें जिससे व्यावसायिक क्षेत्रों में रात में ही सफाई हो जाए।

पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग और रेलवे तक नहीं भर रहे संपत्तिकर

स्वास्थ्य विभाग अकेला ही 83 करोड़ से ऊपर का बकायेदार

ग्वालियर
शहर की सड़कों, सफाई, रोशनी और नालों की व्यवस्था संभालने वाला नगर निगम इन दिनों सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। चुनौती आम नागरिकों से नहीं, बल्कि सरकारी विभागों से है, जो वर्षों से करोड़ों रुपए का संपत्तिकर दबाए बैठे हैं। वर्तमान में नगर निगम की वित्तीय हालत लगातार डगमगाई हुई है। कर्मचारियों के वेतन से लेकर विकास कार्यों तक हर मोर्चे पर खजाना खाली होने की शिकायतें उठ रही हैं।

निगम के राजस्व विभाग के अनुसार, पुलिस विभाग, उच्च शिक्षा, रेलवे, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, कृषि, विधि, राज्य शासन, केन्द्रीय संस्थान और हाउसिंग बोर्ड जैसे 11 सरकारी विभागों पर कुल 220 करोड़ से अधिक का संपत्तिकर बकाया है। अधिकारियों का कहना है कि इन विभागों से टैक्स वसूली के लिए बार-बार नोटिस भेजे गए, बैठकें की



स्वास्थ्य विभाग का सबसे बुरा हाल
नगर निगम के आंकड़े बताते हैं कि स्वास्थ्य विभाग पर लगभग 83 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। इनमें जयरोम्य अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, भगवात सहाय, मेडिकल कॉलेज, रविशंकर छात्रावास, सिविल अस्पताल

हजीरा, एक हजार बिस्तर, कैसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान, माधव चिकित्सालय, मुरार प्रसूति ग्रह। इन अस्पतालों को कई बार नोटिस भेजे गए, मगर बजट स्वीकृति नहीं है कइकर भुगतान टाल दिया गया।

बीएसएनएल उपकेन्द्र, एजी ऑफिस, आकाशवाणी, इंडियन ऑयल आदि का भी कई वर्षों से टैक्स जमा नहीं हुआ।

पुलिस, रेलवे और शासकीय विभाग भी पीछे नहीं

पुलिस विभाग पर लगभग 9 करोड़ रुपए।
रेलवे पर 2 करोड़ रुपए।
लोक निर्माण विभाग पर 2 करोड़ रुपए।
राज्य शासन से जुड़े अन्य कार्यालयों पर 61 करोड़ रुपए बकाया हैं।

केन्द्रीय कार्यालय संस्थान भी पीछे नहीं

केन्द्रीय कार्यालय संस्थानों पर लगभग 24 करोड़ रुपए बकाया है। इनमें नारकोटिक्स कार्यालय,

परिषद का अभियाचित सम्मेलन आज

जीएसटी दरों में कमी और आत्मनिर्भर भारत पर होगा संकल्प

ग्वालियर
नगर निगम परिषद का अभियाचित सम्मेलन 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से जल विहार स्थित परिषद सभागार में आयोजित किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता सभापति मनोज सिंह तोमर करेंगे। इसमें जीएसटी की दरों में कमी और आत्मनिर्भर भारत के संबंध में संकल्प लेने पर चर्चा होगी। महापौर डॉ. शोभा सिकरवार के नेतृत्व में परिषद में सत्ता में कांग्रेस के 24 पार्षद हैं, जबकि भाजपा 42 पार्षदों के साथ विपक्ष में है।



बैठक का एजेंडा विपक्ष की ओर से एक देश-एक चुनाव के मुद्दे पर पेश किया गया है। प्रदेश में नगर निगमों के संदर्भ में यह कदम महत्वपूर्ण है। भोपाल, रतलाम, इंदौर सहित 9 नगर निगमों द्वारा सदन प्रकाश के संकल्प पहले ही पारित किए जा चुके हैं। ग्वालियर में प्रस्तावित अभ्याचित सम्मेलन में भी इसी दिशा में निर्णय लेने की संभावना है।

सरकार के अपने विभागों पर 220 करोड़ का संपत्तिकर बकाया, निगम फिर भी चला रहा शहर

हम जनता से टैक्स वसूल रहे

नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि संपत्तिकर विभाग पर आरोप लगाया जाता है कि वसूली नहीं हो रही। सवाल यह है कि जब सरकार के अपने विभाग ही टैक्स नहीं दे रहे, तो नगर निगम के पास बाकी काम

करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। उन्होंने बताया कि निगम हर साल सरकारी भवनों को नोटिस जारी करता है। कई बार पत्रावली भोपाल तक जाती है, लेकिन वहां से फाइल लौटने में महीनों लग जाते हैं।

वसूली की तैयारी, नोटिस और जब्ती की चेतावनी

नगर निगम ने अब सख्त वसूली अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। विभाग के अनुसार, अगर विभागों ने इस वित्तीय वर्ष में बकाया राशि नहीं चुकाई तो संपत्तियों की जब्ती और सेवा शुल्क रोकने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जौनवार सूची तैयार की जा रही है और प्रमुख सचिवों को भी पत्र भेजे जा रहे हैं।

नगर निगम के खजाने पर सबसे बड़ा सरकारी बोझ
संपत्तिकर वसूली में सबसे बड़ा अड़ंगा सरकारी विभाग ही बन रहे हैं। एक तरफ आम नागरिक या व्यापारी बकाया कर पर जुर्माने तक भर देते हैं, वहीं सरकारी भवनों पर सालों से करोड़ों की देनदारी पड़ी है। निगम को मजबूरी में उन पर भी सेवा जारी रखनी पड़ती है क्योंकि शहर की व्यवस्था रोकना संभव नहीं।

नगर निगम के खर्च और जिम्मेदारियां बढ़ीं

पिछले कुछ सालों में शहर का विस्तार कई गुना बढ़ गया है। सफाई, सीवरज, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, फायर ब्रिगेड जैसी सेवाओं का खर्च लगातार बढ़ा है। ऐसे में अगर सरकारी विभाग अपने हिस्से का कर नहीं देंगे तो वित्तीय संकट और गहराएगा। शहर में प्रतिमाह सिर्फ सफाई व्यवस्था पर ही 20 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आता है, जबकि संपत्तिकर वसूली से औसतन 10-12 करोड़ ही प्राप्त होते हैं।

इनका कहना है

निगम अधिनियम के अनुसार हर संपत्ति चाहे सरकारी हो या निजी को संपत्तिकर देना अनिवार्य है। हमने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। सभी संस्थाओं से संपत्तिकर की वसूली की जाएगी।

संघ प्रिय, निगमयुक्त



सड़क और लाइट व्यवस्था में ढिलाई बर्दाश्त नहीं

ग्वालियर

महापौर डॉ. शोभा सतीश सिंह सिकरवार ने सड़कों और विद्युत व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहर विकास में ढिलाई कतई बर्दाश्त नहीं होगी। महापौर ने कहा कि निगम का पूरा अमला गंभीरता से लगकर कार्य करे, गारंटी पीरियड की सड़कों पर ठेकेदार से तत्काल मरम्मत करवाई जाए और जिन सड़कों पर वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, उन पर तुरंत कार्य प्रारंभ किया जाए।

बाल भवन के टीएलसी में आयोजित बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 42 गारंटी पीरियड सड़कों में से 27 का कार्य पूरा हो चुका है, शेष पर काम प्रगति पर है। महापौर ने कहा कि विलंब किसी भी कारण से न हो, सीवर लाइन या



पीएचई लाइन के कारण देरी हो रही है तो संबंधित अधिकारियों से तुरंत समन्वय कर कार्य पूर्ण कराएं। महापौर ने कहा नवीन सड़कों पर जलभराव न हो, सीवर चेंबर रोड लेवल पर हो, सड़क के दोनों ओर जल निकासी की सड़क प्रबंध हो और कार्य पूर्णता गुणवत्तापूर्ण हो। उन्होंने कहा कि सभी इंजीनियर और अधिकारी गंभीरता से शहर की सड़कों की स्थिति सुधारें, ताकि आने वाले दिनों में ग्वालियर में यातायात सुगम और सड़कों की

स्थिति उत्तम रहे। साथ ही महापौर ने विद्युत व्यवस्था पर भी कड़ा रुख अपनाया। दीपावली के चार-पांच दिन शेष होने पर उन्होंने कहा कि शहर के सभी मुख्य मार्गों पर अंधेरा नहीं रहेगा, इसके लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाए और एक शेड्यूल तैयार किया जाए। सभी वार्डों में बेंडर से तुरंत लाइट मंगाकर समस्या निवारण करें। महापौर ने बैठक में साफ कर दिया है कि ढिलाई करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

सड़कों की पेंच रिपेयरिंग से यातायात सुगम

ग्वालियर। नगर निगम ने बरसात में खराब हुई गारंटी पीरियड और अन्य सड़कों पर तेजी से पेंच रिपेयरिंग का कार्य किया। सहायक यंत्री अमित गुप्ता के अनुसार ऊंट पुल, जटार साहब की गल, आनंद नगर, बाला बाई का बाजार समेत कई प्रमुख स्थानों पर सड़क मरम्मत कर नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित की गई।

बड़े शहरों के निजीकरण की रूपरेखा तैयार, बिजली कार्मिक नाराज

लखनऊ (संवाददाता)। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने आज यहां बताया कि पाँवर कारपोरेशन का शीर्ष प्रबंधन पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के साथ ही पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत सभी बड़े शहरों के निजीकरण की रूपरेखा तैयार कर रहा है। आज इसी योजना के तहत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत गाजियाबाद के दो शहरी क्षेत्र, मुरादाबाद क्षेत्र और सहारनपुर क्षेत्र की प्रशासनिक संरचना के बदलाव के आदेश जारी किए गए हैं। दीपावली के पर्व पर उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति करने हेतु आज उप राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने सभी जनपदों में अभियंताओं की आम सभा की।

त्योहार पर बढ़ी यात्रियों की भीड़

बरौनी की ट्रेनों में जगह नहीं, वंदेभारत व गतिमान में सीटें खाली

ग्वालियर
त्योहारी सीजन में यात्रियों की भारी भीड़ के चलते उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं। ग्वालियर से दिल्ली, गोरखपुर, पटना, मुंबई और पूर्वी क्षेत्रों की ओर जाने वाली ट्रेनों में अब वेटिंग लिस्ट सैकड़ों में पहुंच चुकी है।

ग्वालियर होकर गुजरने वाली वंदेभारत और गतिमान एक्सप्रेस में अभी कुछ सीटें खाली हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनों में जगह नहीं है। रेलवे के अनुसार गतिमान एक्सप्रेस और

वंदेभारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में ग्वालियर से दिल्ली तक करीब 80 से 150 सीटें रोजाना खाली रह रही हैं, जबकि सामान्य और मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में सीटों के लिए लंबी वेटिंग चल रही है। झांसी मंडल के पीआरओ मनोज सिंह के अनुसार दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है।

प्रयागराज से निजामुद्दीन के बीच स्पेशल ट्रेन

त्योहार के अवसर पर यात्रियों



की सुविधा को देखते हुए रेलवे द्वारा प्रयागराज से ग्वालियर होते हुए हजरत निजामुद्दीन तक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन आगामी तीन नवंबर तक संचालित की जाएगी और हर बुधवार व रविवार के हिसाब से कुल छह फेरे लगाएगी। ट्रेन 04123 प्रयागराज से आगामी बुधवार को दोपहर 2:50 बजे प्रस्थान कर शंकरगढ़, डभौरा, मानिकपुर, चित्रकूट,

अतर्रा, बांदा, महोबा, कुलपहाड़, हरयाणपुर, मऊ रामपुर होते हुए रात 22:35 बजे वीरगंगा लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पहुंचेगी। पांच मिनट के ठहराव के बाद ये ट्रेन देर रात 1:05 बजे ग्वालियर आएगी। यहां से धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा, कोसीकला पर ठहराव लेते हुए ट्रेन गुरुवार की सुबह 11:35 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। इसके बाद यहां से ट्रेन क्रमांक 04124 दोपहर 3:45 बजे खाना होकर उसी दिन रात 10:15 बजे ग्वालियर आएगी।

सम्पादकीय

प्रदूषण बड़ी मानवीय आपदा

लौजिए फिर से शीतकाल आ गया और इस समय सभी महानगरों समेत मध्य क्रम के बड़े शहरों में भी पर्यावरण प्रदूषण अपने चरम पर होता है। बच्चे तथा बूढ़े इसके सर्वाधिक शिकार होते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण हर वर्ष हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। यह क्रम हर वर्ष का है लेकिन ना तो आम जनता इसमें सावधानी बरतनी है और ना ही शासन प्रशासन, यह प्रक्रिया लगातार बदस्तुर जारी रहती है। आइये इसकी वर्तमान स्थिति और पर्यावरण प्रदूषण से बचने के उपायों पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय में पर्यावरण और वायु प्रदूषण का संकट भारत जैसे विकासशील देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा है।दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे महानगर आज साँस लेने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। प्रदूषित हवा में नागरिकों की दिनचर्या घुटती जा रही है। दिल्ली, जो विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में गिनी जाती है, वहीं च्छ2.5 का औसत स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ऊपर दर्ज किया गया है कृ जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमा केवल 5 माइक्रोग्राम है। भारत में वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जो किसी मौन महामारी से कम नहीं। राजधानी दिल्ली की वायु में अब वह ठंडक नहीं रही जो कभी यमुना किनारे के पेड़ों की छाँव में महसूस होती थी। हवा में घुला धुआँ और धूल अब बच्चे के खेलते फेफड़ों तक पहुँच चुका है।शहरी नागरिक अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। दिल्ली में अकेले 12 हजार से अधिक मौतें हर वर्ष वायु प्रदूषण से जुड़ी पाई गई हैं। यही नहीं, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बेंगलुरु और हैदराबाद, जो कभी हूहरित नगरहू कहे जाते थे, अब यातायात और औद्योगिक विस्तार की वजह से धुएँ के बादलों में ढके रहते हैं। यह विडंबना है कि हमारे देश में पर्यावरण और राजनीति अब एक-दूसरे के विरोधी शब्द बन गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण पर चर्चा संसद से लेकर सड़कों तक होती है, पर समाधान हाथ नहीं आता। केंद्र और राज्य सरकारें आरोप-प्रत्यारोप में उलझी हैं, जबकि हवा हर दल के मतदाताओं के फेफड़ों में समान रूप से प्रवेश कर रही है। यही स्थिति वैश्विक स्तर पर भी है कृ जहाँ जलवायु परिवर्तन को लेकर सैकड़ों घोषणाएँ होती हैं, पर धरातल पर वनीकरण और स्वच्छ ऊर्जा की गति बेहद धीमी है। आर्थिक विकास के नाम पर मनुष्य ने प्रकृति से जितना लिया, लौटाया बहुत कम। उद्योग, खनन, नदी बाँध और शहरीकरण ने धरती के संतुलन को तोड़ा। पर्वतों को काटा गया, नदियों को बाँधा गया, जंगलों को उखाड़ा गया कृ और अब वही प्रकृति अपने मौन प्रतिशोध में जलवायु परिवर्तन के रूप में खड़ी है। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री जल-स्तर बढ़ रहा है, तूफानों की तीव्रता बढ़ती जा रही है। यह सब संकेत हैं कि प्रकृति अब हूसहनेहूह की सीमा पार कर चुकी है। फिर भी, विकास आवश्यक है पर ऐसा विकास जो टिकाऊ हो, जो जीवन से समझौता न करे। भारत ने हूनेशनल क्लीन एवर प्रोग्राम जैसी योजनाएँ शुरू की हैं जिनका लक्ष्य 2026 तक वायु प्रदूषण को 30: तक घटाना है। यह सराहनीय पहल है, किंतु इसका असर तभी होगा जब नागरिक स्तर पर भागीदारी बढ़े। पर्यावरण संरक्षण को केवल सरकारी जिम्मेदारी मानना भ्रम है। जब तक हर नागरिक अपने घर, वाहन और जीवनशैली को पर्यावरण अनुकूल नहीं बनाता, तब तक हवा का शुद्ध होना असंभव है। हमें अपनी विकास नीति को हरित तकनीक के साथ जोड़ना होगा कृ जैसे ग्रीन एनर्जी, सौर एवं पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन बिल्डिंग, और कार्बन न्यूट्रल उद्योग। यूरोपीय देशों ने यह दिखाया है कि आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण एक साथ चल सकते हैं। वहाँ की नीतियाँ कार्बन टैक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और जनशिक्षा पर आधारित हैं। भारत के लिए भी यही राह अपनाना अनिवार्य है। साथ ही, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ना होगा। यही वह संतुलन है जिससे हम विकास के साथ प्रकृति की गरिमा भी बचा सकते हैं। विकास परियोजनाओं के पूर्व केवल पर्यावरणीय प्रभाव आकलन ही नहीं, बल्कि सामाजिक प्रभाव आकलन को भी अनिवार्य बनाया जाना चाहिए ताकि किसी की भूमि, जीवन या संस्कृति की हानि विकास का मूल्य न बने। आर्थिक और पर्यावरणीय असंतुलन का सबसे बड़ा दुष्परिणाम सामाजिक विभाजन के रूप में सामने आता है। एक ओर महानगरों के लोग सुविधाओं से भरे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण समुदाय अपनी भूमि, जंगल और नदियों से वंचित होकर विस्थापन झेल रहे हैं। यह विकास नहीं, असमानता का विस्तार है। हमें ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें किसी की प्रगति किसी और की हानि पर आधारित न हो।महात्मा गांधी ने कहा था प्रकृति हमारी जस्ूरतों को पूरा करने के लिए है, हमारी लालच को नहीं। आज यह वाक्य एक चेतावनी बन चुका है। यदि हम इस चेतावनी को अनसुना करते रहे, तो आर्थिक विकास की पूरी इमारत उसी प्रकृति की गرخ में समा जाएगी जिसे हमने नींव में रखा था।

भाजपा दलित–जाटव मतदाताओं को लुभाने के लिए उत्तर प्रदेश भर में चौपाल आयोजित करेगी

प्रशांत श्रीवास्तव बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती की प्रशंसा से उत्साहित, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दलित मतदाताओं, खासकर जाटवों को लुभाने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी गैर-आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में चौपाल (पारंपरिक ग्राम सभाएँ) आयोजित करने की योजना बनाई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरूआत करते हुए, भाजपा अपना ध्यान पश्चिमी क्षेत्र पर केंद्रित करने की योजना बना रही है, जहाँ जाटव एक महत्वपूर्ण मतदाता आधार हैं। द्रिप्टि को मिली जानकारी के अनुसार, भाजपा पीडीए (पिछड़े (पिछड़े वर्ग), दलित और अल्पसंख्यक के कथानक का मुकाबला करना चाहती है और दलित मतदाताओं के बीच समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए इसका पूरा नाम परिवार विकास प्राधिकरण प्रस्तुत कर रही है। पाटी नेताओं का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य यह उजागर करना है कि मायावती, जो राज्य की सबसे प्रमुख दलित नेता हैं, भी भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों को स्वीकार करती हैं और उनकी सराहना करती हैं। भाजपा की यह योजना तब

●●●●●

महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के बाद बिहार- राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं?



लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सहयोगी दलों के समर्थन के बल पर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री तो बन गए लेकिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार विपक्षी गठबंधन को इतनी ज्यादा सीटें दिलाने का श्रेय लेकर कांग्रेस ने राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित करने का प्रयास किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में सहयोगी दलों की मदद से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए राहुल गांधी ने उस यूपीए के नाम को भी त्याग दिया जिसके बैनर तले कांग्रेस ने वर्ष 2004 से 2014 तक देश में राज किया था। लोकसभा चुनाव से पहले यूपीए की जगह पर राहुल गांधी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक नया मोर्चा बनाया जिसे इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सहयोगी दलों के समर्थन के बल पर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री तो बन गए लेकिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार विपक्षी गठबंधन को इतनी ज्यादा सीटें दिलाने का श्रेय लेकर कांग्रेस ने राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित करने का प्रयास किया। कुछ हद तक कांग्रेस को अपने इस अभियान में कामयाबी मिलती भी दिखाई दी। वोट चोरी का अभियान चला कर और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल कर राहुल गांधी अपने आपको विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर स्थापित करने में

थोड़े बहुत कामयाब होते भी दिखाई दिे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा मुखिया अखिलेश यादव से

है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट और विधानसभा

के चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस आमने-

है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट और विधानसभा

चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस आमने-

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो खुलकर राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार तक बता दिया। लेकिन इन सबके बावजूद अचानक देश की राजनीति तेजी से बदलती हुई नजर आने लगी है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस आमने–सामने आ गए हैं। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसदों के लिए होने वाले चुनाव में उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने तीनों सेफ सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और कांग्रेस को जो चौथी सीट ऑफर की है, उसे जीतना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस पहले से ही इसे लेकर अपने सहयोगी दल से नाराज चल रही है वहीं अब विधानसभा की जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसे लेकर भी मामला फंसता हुआ ही नजर आ रहा है। राज्य में विधानसभा की 2 सीटों– बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को चुनाव होना है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हामिद करी ने उमर अब्दुल्ला की पार्टी पर गठबंधन के सिद्धांतों का अनादर करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह राज्यसभा की एक सेफ सीट देने के अपने वादे से मुकर गई। कांग्रेस ने गठबंधन धर्म की याद दिलाते हुए सख्त शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो नेशनल कांफ्रेंस उन्हें विधानसभा की एक सीट दे या फिर कांग्रेस दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देगी। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव के समय से ही शुरू हुई खटास कम होने का नाम नहीं ले रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और दुनिया भर में भेजे गए सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर एनसीपी और कांग्रेस के सुर अलग–अलग तो नजर आए ही। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद इस्तीफे की बाध्यता वाले बिल पर गठित की जाने वाली जेपीसी में शामिल नहीं होने को लेकर भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों को अपने साथ ला पाने में नाकामयाब होती नजर आ रही है। वहीं बिहार का मामला तो राहुल गांधी के नेतृत्व की स्वीकार्यता को लेकर सबसे बड़ा झटका साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आरजेडी है जिसके नेता तेजस्वी यादव ने खुल कर राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का समर्थन कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो लगातार पूछे जाने के बावजूद भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे हैं। जबकि राजनीतिक सच्चाई तो यही है कि बिहार में विपक्षी गठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस और आरजेडी में सीटों के बंटवारे को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस

लेकर तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एवं डीएमके सुप्रियो स्टालिन तक से उनके व्यक्तिगत संबंध मजबूत होते नजर आए। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव जीतने में राहुल गांधी और नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला की व्यक्तिगत केमिस्ट्री का जबरदस्त योगदान माना जाता है। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो खुलकर राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार तक बता दिया। लेकिन इन सबके बावजूद अचानक देश की राजनीति तेजी से बदलती हुई नजर आने लगी

सामान्य पटाखे बनाम ग्रीन पटाखे



बारिश खत्म होते ही, ठंड की हल्की दस्तक के साथ प्रदूषण का अनचाहा आगमन भी हो चुका है। साल दर साल बीतेते जा रहे हैं और प्रदूषण की समस्या से निजात ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसकी जड़ों तक जाने की कोशिश ही नहीं हो रही है। केवल ऊपरी तौर पर नियम बनाकर प्रदूषण जैसी गंभीर और जटिल समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, ये बात नीति नियंता भी अच्छे से जानते हैं। मगर शायद प्रदूषण दूर करना उनके लिए जीने–मरने का सवाल कभी रहा ही नहीं। उन्हें वातायुक्कृत दफ्तरो में बैठकर काम करना है, तमाम सुविधा–संपन्न घरों में रहना है, छुट्टियों पर प्रदूषण रहित पर्यटक स्थलों पर वे जाते हैं और अगर बीमार पड़ें तो सात सितार अस्पतालों में महंगा इलाज उनके लिए उपलब्ध

है। लेकिन आम आदमी प्रदूषण की मार बारह महीने झेलता है, फिर भी समझ नहीं पाता कि उसे खुश करके आखिर में उसे ही धीरे–धीरे मारने का इंतजाम किया जा रहा है। दीपावली से पहले सुप्रिम कोर्ट ने हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग की जो इजाजत दी है, वो इसी धीमी मौत का एक और उदाहरण है। सुप्रिम कोर्ट को कम नुकसानदायक पटाखों को जलाने की मंजूरी इसलिए देनी पड़ी क्योंकि दीपावली अब रोगानी, रंगों और मिठास से ज्यादा उस हिंदुत्व का त्योहार बन चुका है, जिसे अपने प्रचार के लिए कानफेड्यू शोर की जरूरत पड़ती है। न जाने किस तरह बहुतेरे हिंदुओं के दिमाग में यह बात भर दी गई कि दीपावली पर पटाखे जलाने से रोकना धर्म का अपमान है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भाजपा का इस मुहिम में बड़ा योगदान रहा। प्रभावमंत्री मोदी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान बांटते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों और समर्थकों को यह नहीं समझा सकते कि धर्म की राजनीति चलती रहेगी, कम से कम त्योहार को इसमें वखड़ा दें। अगर आज मोदी लोगों से अपील करें कि वे पटाखे न जलाएँ, दीप, कंदील जलाकर, रंगोली सजाकर दीवाली मना लें, तो उनके अनुयायी खुशी–खुशी इस बात को मानेंगे। जब बालकनी में आकर थाली पीट सकते हैं, तो ये काम भी कर ही सकते हैं। मगर मोदी को भी ये डर है कि हिंदुत्व के नाम पर जिन लोगों को पूरी तरह गुमराह किया जा चुका है, वे इस बात को गलत तरीके से ले कर अपनी नाराजगी मोदी पर ही उतार सकते हैं। इसलिए भाजपा में अब पटाखों की नहीं, ग्रीन यानी हरित पटाखों की बात होती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रिम कोर्ट का आभार

माना है कि उसने इन पटाखों के लिए मंजूरी दी। शीर्ष अदालत ने सिर्फ नीरी (नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी है। जो केवल 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए दी गई है। अदालत ने साफ किया कि इस अवधि के बाद किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल पर प्रतिबंध जारी रहेगा। अगर कोई विक्रेता या निमाता इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भी दिया गया है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर विशेष निगरानी दल गठित करें। इन टीमों का काम यह सुनिश्चित करना होगा कि सिर्फ प्रमाणित ग्रीन पटाखों का ही निर्माण, बिक्री और उपयोग हो रहा है। अदालत ने पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए पटाखे फोड़ने की समय सीमा सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 8 बजे से 10 बजे तक तय की है। इन समय सीमाओं के बाहर किसी भी प्रकार के पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित रहेगा। यह पूरा आदेश सुनने में प्रभावशाली लगता है, लेकिन जमीन पर इसका असर शून्य बसावर होने की संभावना है। क्योंकि अभी से दिल्ली–एनसीआर में जमकर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। अवैध तरीकों से बिक्री होने की खबरें हैं और प्रदूषण भी खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है। पिछले साल भी ऐसा ही आलम था और लगातार कई सालों से यही होता आया है। इसलिए ग्रीन पटाखे दिल को खुश रखने के ख्याल से ज्यादा और कुछ मायने नहीं रखते। अर्थात तौर पर सब इस बात को जानते हैं कि ग्रीन पटाखों का लेबल लगाकर पारंपरिक पटाखे ही बेचे जाते हैं। क्योंकि लागत में ये सस्ते पड़ेंगे हैं। विशेष निगरानी दल बनाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि दीपावली के सामान से अटे पड़े बाजार में अब इस बात की जांच बेहद मुश्किल होगी कि कौन से सही में ग्रीन पटाखे हैं और कौन से नहीं। बल्कि इस जांच के नाम पर अवैध कमाई का एक और रास्ता खुल जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

विकास दर की लय

जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ पर पश्चिमी शक्तियों के मंसूखों के अनुरूप सुर में सुर मिलाने का आक्षेप लगता रहा है, यदि वह अब भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर दर्शाए तो इसे हम अपनी आर्थिकी की ताकत के रूप में देख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि आईएमएफ ने वर्ष 2025–26 के लिये भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.6 कर दिया है। इस नवीनतम अपडेट से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में देश की स्थिति और मजबूत हुई है। दरअसल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह संशोधन लचीली घरेलू खपत, मजबूत सेवा निर्यात और स्थिर सार्वजनिक निवेश के दृष्टिगत किया है। यह सुखद ही कहा जाएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मनमाने और भारी-भरकम टैरिफ का कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर दृष्टिगोचर नहीं होता है। लेकिन इस आशावाद के बावजूद हमें अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य की वास्तविकता का भी ध्यान रखना चाहिए। जिसके मूल में तमाम व्यापारिक व्यवधान, अमेरिकी टैरिफ वृद्धि और सख्त वित्तीय स्थितियों जैसे घटक भी शामिल हो सकते हैं। जो प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कहीं न कहीं भारत की आर्थिक गति को प्रभावित कर सकते हैं। निर्विवाद रूप से भारत की अर्थव्यवस्था में आईएमएफ का भरोसा, मजबूत भारतीय घरेलू बाजार, राजकोपीय अनुशासन और औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता में

●●●●●

वृद्धि के उद्देश्य से किए गए सुधारात्मक उपायों के चलते जगा है। वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे पर खर्च, डिजिटल परिवर्तन को प्रोत्साहन और बेहतर कर संग्रह ने व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत ही किया है। हालांकि निर्यात, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र, संरक्षणवादी नीतियों और कमजोर वैश्विक मांग के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर चीन की मंदी और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्संतुलन के साथ, भारत के सामने चुनौती और अवसर दोनों ही मौजूद हैं। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वह वैश्विक व्यापार में संतुलन बनाते हुए आत्मनिर्भरता की राह में कदम आगे बढ़ाए। इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था की मौजूदा चुनौती को महसूस करते हुए मेक इन इंडिया की मुहिम को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास एक आंदोलन के रूप में किया है। दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा मेक इन इंडिया अभियान के तहत विनिर्माण पर खासा जोर दिया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार की प्राथमिकता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, सेमीकंडक्टर और हरित प्रौद्योगिकियों के लिये लक्षित प्रोत्साहनों को बढ़ावा देना है। निस्संदेह ये प्रयास कालांतर देश के औद्योगिक आधार को व्यापक रूप से मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम अल्पकालिक लक्ष्यों के बजाय दीर्घकालीन जरूरतों को

●●●●●

अपनी प्राथमिकता बनाएँ। इसके लिये जरूरी है कि श्रम बाजार, भूमि अधिग्रहण में सुधार और व्यापार में कामकाज को आसानी को बढ़ावा दें। निस्संदेह, इन क्षेत्रों में गहन संरचनात्मक सुधारों की सख्त आवश्यकता होगी। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की प्राथमिकता मुद्रास्फूर्ति पर नियंत्रण की भी होनी चाहिए। महंगाई के बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति प्रभावित होती है, जिससे मांग व पूर्ति का संतुलन बिगड़ता है। वहीं दूसरी ओर कृषि उत्पादकता और रोजगार सृजन को भी नीतिगत एजेंडे के केंद्र में रखना चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि आज भारत की आर्थिक सफलता की कहानी हमारे सतर्क आत्मविश्वास की परिणति है। देश की घरेलू अर्थव्यवस्था के लचीलेपन ने इसे कई भारी झटकों से बचाया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारी आत्मसंतुष्टि इस लाभ को कम सकती है। इसके अलावा दीर्घकालिक स्थिरता के लिये, भारत सरकार को राजकोपीय विवेक बनाए रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ मानव पूंजी, उत्पादकता और नवाचारी में निवेश को बढ़ााना होगा। निस्संदेह, हमारा विकास तभी साक्षीक होगा जब वह समावेशी हो। वह देश के लाखों गरीब लोगों को ऊपर उठाने में सक्षम हो, न कि केवल सिर्फ सांख्यिकीय संकेतकों को बढ़ावा देने वाला हो। हमारी आर्थिक यात्रा में निरंतर स्थिरता बनी रहे, इसके लिये देश को आर्थिक सुधार की राह चुननी होगी।



घरेलू बचत में बदलाव भारत के आर्थिक भविष्य की दिशा तय करेगा, एलारासिक्वोरिटीज की रिपोर्ट में दावा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की महत्वाकांक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि देश अपने घरों की बचत को कितनी प्रभावी ढंग से उत्पादक संपत्तियों में लगाता है। यह बात एलारासिक्वोरिटीज की हालिया रिपोर्ट में कही गई है। आने वाले वर्षों में बदलाव की संभावना रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में घरेलू बचत की संरचना में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। यह बदलाव अनुकूल जनसांख्यिकी, सरकारी सुधार, आर्थिक नीतियां और मजबूत डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा समर्थित है। ये सभी कारक आने वाले वर्षों में भारतीय घरों के बचत और निवेश के तरीके में स्पष्ट बदलाव लाने की संभावना रखते हैं। अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की स्थिति रिपोर्ट ने कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के लिए घरेलू बचत को उत्पादक संपत्तियों की ओर निर्देशित करना आवश्यक है।

जीवन अनिश्चित लगने पर 'योग' की ओर लौटीं मनीषा कोइराला

वीडियो शेयर कर बताई सच्चाई



मनीषा कोइराला ने आज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक खास वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में मनीषा योगा करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो के साथ मनीषा ने अपने फैंस को एक खास सीख भी दी है। प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने जीवन की अनिश्चितता और उलझनों से निपटने का अपना तरीका बताया है। उन्होंने बताया कि कैसे समय में वे योग की ओर मुड़ती हैं। योग उनके लिए सिर्फ व्यायाम नहीं, बल्कि घर लौटने जैसा है। मनीषा का पोस्ट मनीषा ने इंस्टाग्राम पर योग करते अपनी एक तस्वीरें शेयर कीं। इसमें वह सुखासन करती दिख रही हैं। उन्होंने लिखा, 'जब जीवन अनिश्चित लगे और मन

भटके, तो मैं शांति की तलाश करती हूं। योग में संतुलन मिलता है, जो मैं दृढ़ता नहीं, बल्कि लौटकर पाती हूं।' नारी को लेकर मनीषा के विचार नारीत्व पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'नारीत्व आसान नहीं होता। यह जीवन, दोस्ती और गरिमा के साथ उग्र बढ़ाने के बारे में है। हमें ऐसे लोग चुनने चाहिए जो हमारे जीवन में मतलब जोड़ें।' मनीषा का करियर 54 साल की मनीषा को आखिरी बार संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' में देखा गया। यह वेब सीरीज आजादी की लड़ाई के समय लाहौर के हीरा मंडी इलाके पर आधारित है। इसमें तवायफों की जिंदगी और उनके संघर्ष दिखाए गए

हैं। मनीषा अपने समय की सबसे पॉपुलर और कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने 1989 में नेपाली फिल्म 'फेरी भेटौला' से करियर शुरू किया। 1991 में हिंदी फिल्म 'सौदागर' से बॉलीवुड में आईं। उन्होंने 'बॉम्बे', 'अग्नि साक्षी', 'खामोशी: द म्यूजिकल', 'दिल से..', 'कंपनी' और 'लज्जा' जैसी फिल्मों में काम किया। बाद में 'एक्सेस प्रेम तालिबान' और 'आई एम' जैसी अलग तरह की फिल्मों कीं। 2012 में उन्हें ओवेरियन कैंसर हुआ, जो आखिरी स्टेज में था। एक साल इलाज चला। 2014 तक वे ठीक हो गईं और फिर 2017 में 'डियर माया' से वापसी की। वह जल्द ही 'हीरामंडी 2' में नजर आएंगी।



पंकज धीर के अंतिम संस्कार में बेटे का रो-रोकर बुरा हाल, सलमान खान ने गले लगाकर दिया हौसला

बॉलीवुड और टीवी के दिग्गज एक्टर पंकज धीर अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका 15 अक्टूबर को

दिखे। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि पंकज धीर के अंतिम संस्कार में पहुंचे सलमान

प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। बता दें, पंकज धीर लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे।

आर. चोपड़ा के टीवी शो महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाई। यह किरदार आज भी भारतीय



कैंसर के चलते निधन हो गया। वहीं, बीते दिन ही उनका अंतिम संस्कार भी किया गया, जहां फिल्म और टीवी जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं। वहीं, पिता पंकज को अंतिम विदाई देते वक्त उनके बेटे निकितन बुरी तरह दूट गए और फूट-फूटकर रोते नजर आए। इस मौके पर एक्टर सलमान खान उन्हें गले लगाकर ढाँस बंधाते

खान इस दौरान उनके बेटे निकितन को गले लगाकर हौसला देते दिखे। इसके बाद भी एक्टर ने चंद मिनट तक निकितन का हाथ नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, सलमान खान ने पंकज धीर के दोस्तों और एक्टर मुकेश तिवारी को भी गले से लगाकर दुख बांटा। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और यूजर्स इस पर अपनी

बीमारी के कारण उनकी सेहत लगातार कमजोर हो रही थी और इलाज के बीच ही एक्टर 15 अक्टूबर को इस दुनिया को अलविदा कह गए। पंकज धीर का एक्टर सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने 1980 के दशक में फिल्मों में छोटे-छोटे रोल्स से करियर की शुरुआत की थी। उनका बड़ा ब्रेक 1988 में तब आया जब उन्होंने बी.

टेलीविजन के सबसे यादगार पात्रों में से एक माना जाता है। इसके बाद उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों जैसे बादशाह, जमीन, तुमको ना भूल पाएंगे, और सैनिक में अहम भूमिकाएं निभाईं। टीवी जगत में भी पंकज धीर का योगदान उल्लेखनीय रहा। उन्होंने ससुराल सिमर का, राजा की आएगी बारात, और कई अन्य धारावाहिकों में अभिनय किया।

पति जहीर इकबाल ने दिया सोनाक्षी सिन्हा की प्रेग्नेंसी का हिंट ! पेट पर हाथ रखते ही चिल्ला पड़ीं एक्ट्रेस



एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल संग पिछले साल जून में शादी रचाई थी। अब कपल की शादी को एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और अक्सर दोनों के पेरेंट्स बनने की रुमर्स सोशल मीडिया पर उड़ती रहती हैं। कई बार यूजर्स कयास लगा चुके हैं कि सोनाक्षी मां बनने वाली हैं। मगर वह मजेदार अंदाज में इन अफवाहों को हर बार खारिज कर ही देते हैं। वहीं, हाल ही में एक पार्टी से दोनों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख फिर से एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी की अफवाहें उड़ने लगीं। दरअसल, सोनाक्षी सिन्हा हाल

ही में अपने पति जहीर इकबाल के साथ एक पार्टी में शामिल हुईं। इस दौरान एक्ट्रेस ने आइवरी कलर की ढीली-ढाली ड्रेस पहनी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। सोनाक्षी और जहीर के साथ इस दौरान सोहेल खान और अरबाज खान के बेटे निर्वाण और अरहान खान भी नजर आए। जब फोटो सेशन हुआ तो जहीर ने मजाकिया अंदाज में सोनाक्षी सिन्हा के पेट पर हाथ रखकर पैस को पोज देने की कोशिश की, जिससे एक्ट्रेस हैरान रह गईं और एकदम चिल्ला उठीं। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा जहीर और उछल कर पीछे हो गईं। इस पर

जहीर कहते हैं 'मजाक था। जहीर इकबाल का ये प्रैंक देख जहां कई लोग हंस रहे हैं तो वहीं, कई यह मान रहे हैं कि वह हिंट दे रहे हैं कि एक्ट्रेस वाकई मां बनने वाली हैं। हालांकि, कपल ने अभी तक कोई प्रेग्नेंसी की पुष्टि नहीं की है। सोनाक्षी सिन्हा हाल ही में वेब सीरीज हीरामंडी में नजर आई थीं, जिसमें उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई। इसके अलावा वह जल्द ही कुछ नए प्रोजेक्ट्स में भी नजर आने वाली हैं। जहीर इकबाल भी बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने में जुटे हुए हैं और आने वाले समय में उनकी एक नई फिल्म की चर्चा चल रही है।

अनुपमा की रुपाली ने स्टेज पर किया

खुलासा, कहा बेटे की असली मां मेरे पति हैं

स्टार प्लस के लोकप्रिय शो अनुपमा की अभिनेत्री रुपाली गांगुली ने हाल ही में अपने निजी जीवन से जुड़ी एक इमोशनल घटना साझा की है। हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें उनके रियल लाइफ बेटे रुद्रांश से बेस्ट मॉम का अवॉर्ड मिला, जिसके बाद उन्होंने अपने काम और परिवार के बीच संतुलन



बनाए रखने की चुनौतियों पर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने अपने पति अश्विन वर्मा की भी जमकर तारीफ की, जिनके सामने अश्विन भावुक होकर हाथ जोड़ते नजर आए। हाल ही में स्टार प्लस पर आयोजित कार्यक्रम में रुपाली गांगुली को उनके रियल लाइफ बेटे रुद्रांश से बेस्ट मॉम का अवॉर्ड मिला। अवॉर्ड लेते समय रुपाली काफी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, 'हमैंने अपने बेटे को बड़ा होते देखा ही नहीं। अनुपमा बनने के लिए मैं उसे वक्त नहीं दे पाई। हर मां जो काम पर जाती है, उसके दिल में कहीं न कहीं ये गिल्ट जरूर होता है कि वह अपने बच्चे को बड़े होते नहीं देख पाती। अवॉर्ड मिलने के बाद रुपाली ने पति अश्विन वर्मा की भी दिल से तारीफ की। उन्होंने कहा, 'हूअगर मेरी असली जिंदगी में फेक्टोर्ट मां का अवॉर्ड किसी को मिलना चाहिए तो वह मेरे पति अश्विन को मिलना चाहिए।' इस बात पर अश्विन भावुक हो गए और पत्नी के सामने हाथ जोड़कर उनकी बातों को सम्मानित किया। रुपाली ने कहा कि भगवान, स्टार प्लस और शो के निमाता राजन शाही की कृपा से उन्हें अनुपमा बनने का मौका मिला और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। हालांकि उन्हें अपने बेटे के साथ कम समय बिताने का गिल्ट रहता है, लेकिन उनका परिवार के लिए समर्पण सदैव कायम है।

सुपरस्टार महेश बाबू आज करेंगे

जटाधारा का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक जटाधारा को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच जी स्टूडियोज और प्रेरणा अरोड़ा ने फिल्म का शानदार मोशन पोस्टर जारी करते हुए घोषणा की है कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर 17 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा, जिसे सुपरस्टार महेश बाबू हैदराबाद में रिलीज करेंगे। गौरतलब है की हाल ही में रिलीज हुई रहस्यमयी, शक्तिशाली और बेहद प्रभावशाली मोशन पोस्टर



अपने आप में एक विजुअल स्टॉर्म हैं, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा अपने अब तक के सबसे बोलूड और दमदार अवतार में नजर आ रही हैं। फिलहाल सोनाक्षी जहां प्रखर ऊर्जा से भरपूर, दिव्यता और शक्ति का संगम लग रही हैं, वहीं सुधीर बाबू अपनी तराशी हुई बॉडी, पैनी नजर और त्रिशूल के साथ अच्छाई और बुराई के अनंत संघर्ष का प्रतीक नजर आते हैं। जी स्टूडियोज और प्रेरणा अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत जटाधारा एक द्विभाषी सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर हैं। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा के साथ दिव्या खोसला, शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी, रोहित पाठक, झांसी, राजीव कनकला और सुभलेखा सुधाकर जैसे शानदार कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। साथ ही साथ ही जी म्यूजिक कंपनी के साउंडट्रैक से सजी फिल्म जटाधारा सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि आस्था, नियति और प्रकाश-अंधकार के अंत में युद्ध की एक महागाथा है, जो 7 नवंबर 2025 को हिंदी और तेलुगु में देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'मुझे बांधा, प्रताड़ित किया और धमकाया'

ग्रेटा थनबर्ग ने इस्त्राइली 'यातना' पर अब तोड़ी चुप्पी

तेल अवीव (एजेंसी)। फलस्तीनियों के लिए राहत सामग्री ले जाने के दौरान इस्त्राइल ने अंतराष्ट्रीय पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग को हिरासत में लिया था। जिसके बाद अब थनबर्ग ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में खुलकर बात की, जब उन्हें फ्रीडम फ्लोटिला में हिस्सा लेने के बाद इस्त्राइली अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। इस फ्लोटिला का उद्देश्य गाजा में नाकाबंदी के तहत फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता पहुंचाना था। हालांकि, इस महीने की शुरुआत में इस्त्राइली बलों ने इस मिशन को रोक दिया, और वॉटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए कई जहाजों पर चढ़े और 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। हाई

गिरफ्तारी के बाद इस्त्राइली हिरासत में यातना के गंभीर आरोप लगाए। ग्रेटा थनबर्ग ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के बारे में खुलकर बात की, जब उन्हें फ्रीडम फ्लोटिला में हिस्सा लेने के बाद इस्त्राइली अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। इस फ्लोटिला का उद्देश्य गाजा में नाकाबंदी के तहत फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता पहुंचाना था। हालांकि, इस महीने की शुरुआत में इस्त्राइली बलों ने इस मिशन को रोक दिया, और वॉटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए कई जहाजों पर चढ़े और 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। हाई

सिक्वोरिटी जेल में रखा, धमकाया ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथी कार्यकर्ताओं को हाई सिक्वोरिटी



वाली जेल में रखा गया था। उन्हें कई दिनों बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन अब उनका दावा है कि हिरासत के दौरान उन्हें शारीरिक शोषण, धमकियां और उत्पीड़न का सामना

करना पड़ा। अब ग्रेटा थनबर्ग ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, धमकाया और परेशान किया, जिसमें उन्हें बांधना और फिर सेल्फी लेना भी शामिल था। 'मुझे बांधा, प्रताड़ित किया और सेल्फी ली'

याद नहीं है। वे मुझे घसीटकर उस तरफ ले गए जहां दूसरे लोग बैठे थे, और पूरे समय मेरे चारों ओर झंडा लटका हुआ था। उन्होंने मेरी पिटाई की और लात मारी। उन्होंने आगे कहा, एक साथ इतना कुछ हो रहा होता है। आप सदमे में होते हैं। आपको दर्द होता है, लेकिन आप शांत रहने की कोशिश करते हैं' थनबर्ग ने बताया कि उन्होंने लगभग 50 लोगों को घुटनों के बल, हथकड़ी लगे और जमीन पर माथे रखे देखा। उन्होंने दावा किया कि इस्त्राइली गार्डों ने उनके हाथों को कसकर बांधा और जब वह शांत हो गई तो उनके साथ सेल्फी लेने के लिए कतार में खड़े हो

गए थे। थनबर्ग ने यह भी आरोप लगाया कि एक समय तो बंदियों को गैस से मारने की धमकी भी दी गई थी। उन्होंने कहा कि फिर गार्ड आए और कहा, 'हम तुम्हें गैस से मार देंगे।' ऐसा कहना उनके लिए आम बात थी। उन्होंने एक गैस सिलेंडर दिखाया और धमकी दी। थनबर्ग ने जोर देकर कहा कि ध्यान नाकाबंदी और अकाल से जूझ रहे फलस्तीनियों की नाकाबंदी पर होना चाहिए, ना कि उनके व्यक्तिगत अनुभव पर। उन्होंने कहा, व्यक्तिगत रूप से मैं यह नहीं बताना चाहती कि मेरे साथ क्या हुआ? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यह सुर्खियां बने।

'सेना को विरोधी न बनाएं, लोकतंत्र के लिए संतुलन बनाए रखें'; बीएनपी ने यूसुफ सरकार को किया आगाह

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अंतरिम प्रमुख युनुस को सेना के साथ विवाद टालने की चेतावनी दी। पार्टी का समर्थन सीमित और शर्तों के साथ है। बांग्लादेश की मुख्य राजनीतिक पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनुस को सेना के साथ किसी भी तरह के टकराव से बचने की चेतावनी दी। पार्टी के स्थायी समिति सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने आपातकालीन बैठक में कहा हम चाहते हैं कि आप सशस्त्र बलों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। राज्य को संतुलित स्थिति में रखना आवश्यक है। सुझा और राजनीतिक संतुलन पर जोर अहमद ने बताया कि आगामी फरवरी 2026 के आम चुनाव से पहले किसी भी तरह का जोरिम पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने चेताया कि पूर्व नेतृत्व और उनके सहयोगी अवामी लीग सेना और अंतरिम सरकार के बीच मतभेदों का फायदा उठा सकते हैं। कच्छ-इऊट्रयल और गिरफ्तारी वारंट बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पिछले हफ्ते 16 सक्रिय सेना अधिकारियों और 14 अन्य व्यक्तियों, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल हैं, के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आरोप उनके कथित राजनीतिक विरोधियों की अगवा और यातना में शामिल होने के हैं। सेना ने 16 में से 15 अधिकारियों को हिरासत में लिया, जबकि वारंट की कोई प्रति नहीं मिली। सरकार ने ढाका कैबिनेटमेंट में एक इमरत को अस्थायी जेल घोषित किया।



'बर्दाश्त नहीं किया जा सकता'

संघीय कर्मियों के नौकरी से निकाले जाने पर जज की ट्रंप प्रशासन को फटकार

वॉशिंगटन (एजेंसी)। सैन फ्रांसिस्को की जिला न्यायाधीश सुजन इल्स्टन ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से 4,100 से अधिक कर्मचारियों को हटाने का निर्णय कानूनी अधिकार से परे है और इससे मानवीय नुकसान हो रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत के जज ने बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को सरकारी कामकाज बंद (शटडाउन) के दौरान हजारों कर्मचारियों को सेवाएं समाप्त करने से अस्थायी रूप से रोक दिया। अदालत ने कहा कि यह कदम राजनीतिक मकसद से प्रेरित दिखता है और बिना सही तैयारी के उठाया गया है। गौरतलब है कि अमेरिका में यह

शटडाउन का तीसरा हफ्ता है। सैन फ्रांसिस्को की जिला न्यायाधीश



सुजन इल्स्टन ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से 4,100 से अधिक कर्मचारियों को हटाने का निर्णय कानूनी अधिकार से परे है और इससे मानवीय नुकसान हो रहा है। उन्होंने इस फैसले

को रोकते हुए अस्थायी प्रतिबंध आदेश जारी किया। इल्स्टन ने सुनवाई के दौरान सरकारी वकील से बार-बार यह पूछने की कोशिश की कि जब ज्यादातर प्रभावित कर्मचारी पहले से ही फलों (अस्थायी छुट्टी) पर हैं और उनकी ईमेल या मानव संसाधन सहायता तक पहुंच नहीं है, तो ऐसे में यह छंटनी क्यों की जा रही है।

न्यायाधीश ने कहा, यह बहुत हद तक पहले गोली चलाओ, फिर निशाना लगाओ जैसी नीति है, जो अस्वीकार्य है। यह आदेश अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों के संगठन अमेरिकन

फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और अन्य संघों की याचिका पर आया, जिन्होंने अदालत से मांग की थी कि सरकार को नए छंटनी नोटिस जारी करने और पहले से दिए गए नोटिस लागू करने से रोका जाए। उनका कहना था कि यह कार्रवाई कर्मचारियों को सजा देने और कग्रेस पर दबाव बनाने का राजनीतिक प्रयास है। व्हाइट हाउस ने इस पर टिप्पणी से इनकार करते हुए कहा कि इस विषय में सभी सवाल प्रबंधन और बजट दफ्तर से किए जाएं, जिसने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। डेमोक्रेट सांसद चाहते हैं कि सरकारी कामकाज दोबारा शुरू करने से पहले स्वास्थ्य बीमा सॉल्यूशंस को जारी रखने और मैडिकेड कटौती को

वापस लेने पर सहमति बने, जबकि रिपब्लिकन स्पीकर माइक जॉनसन ने डेमोक्रेट्स की सुनवाई से इनकार किया है। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन आठ संघीय एजेंसियों में 4,100 से अधिक पदों को समाप्त करने की योजना बना रहा है। यह कटौती मुख्य रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा कार्यक्रमों में की जा रही है, जबकि सेना और आब्रजन नियंत्रण के खर्च जारी हैं। इससे पहले भी न्यायाधीश इल्स्टन ने संघीय कार्यबल को घटाने की प्रशासन की कोशिशों पर रोक लगाई थी, हालांकि बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक कर्मचारियों की छंटनी की अनुमति दे दी थी।

चीन के चोर बाजार में भारत सहित इन देशों के

आईफोन की बाढ़; इस कारण बढ़ी अवैध मांग

बीजिंग/नई दिल्ली (एजेंसी)। एशियाई खुफिया एजेंसियों के अनुसार बीजिंग, शेन्जेन और ग्वांगडू के बीच सक्रिय एक संगठित नेटवर्क हर महीने 2.5 से 3 लाख चोरी के फोन विभिन्न चैनलों से चीन लाता है। इनमें से 40% से अधिक फोन भारत,



नेपाल, थाईलैंड और इंडोनेशिया से चोरी होकर पहुंचते हैं। शेन्जेन के काले बाजारों में ये फोन ग्री-ग्राम्प्राइड होते हैं यानी नया आईफोनआई नंबर और अनलॉकड आईक्लाउड के साथ बेचे जाते हैं। चीन में सोशल मीडिया पर सरकारी प्रतिबंध और आईफोन की आसमान छूती कीमतों ने एक नए ब्लैक टेक मार्केट को जन्म दे दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, चीन में बिकने वाले कुल मोबाइल फोनों में से लगभग 12 से 15% तक अब अवैध या चोरी के माध्यमों से बाजार में आने वाले उपकरणों का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें से अधिकतर फोन भारत, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों से चोरी होकर पहुंचते हैं। इस बढ़ते नेटवर्क को रोकने में भारत का सी-डॉट व उसकी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर प्रणाली अब एक निर्णायक तकनीकी मॉडल के रूप में उभर रही है। चीन में आईफोन सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं बल्कि प्रतिष्ठा (स्टेटस सिंबल) का प्रतीक बन चुका है। निक्केई एशिया के अनुसार बीजिंग और शंघाई के युवाओं में आईफोन रखना पश्चिमी जीवनशैली और आर्थिक सफलता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन समस्या यह है कि चीन में औसत शहरी आय 8 से 10,000 युआन प्रति माह है, जबकि आईफोन के नए मॉडलों की कीमत 10,000 से 14,000 युआन तक है। चोर बाजार में ये मोबाइल 30 से 40% सस्ते मिल जाते हैं।

व्हाइट हाउस बालरूम के लिए चंदा जुटाने के लिए ट्रंप ने दी भव्य डिनर पार्टी, जानें कौन-कौन अरबपति हुए शामिल

वॉशिंगटन (एजेंसी)। डिनर पार्टी के खाने के मेन्यू में कई खास डिश परोसीं गईं, जिनमें टैपेटो पेजानेला सलाद, वीफ वेलिंग्टन, नाशपाती, दालचीनी की मिठाई और बटरस्क्वॉच आइसक्रीम



आदि शामिल रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में एक आलीशान डिनर पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में अमेरिका के अरबपति कारोबारी और धनी व्यक्ति

शामिल हुए। यह पार्टी व्हाइट हाउस में नए बालरूम के निर्माण के लिए चंदा जुटाने के लिए आयोजित की गई थी। इस पार्टी में करीब 130 हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि और डिग्ज निवेशक शुमार रहे। 25 करोड़ डॉलर की लागत से बनाया गया बालरूम व्हाइट हाउस में नए बालरूम के निर्माण में करीब 25 करोड़ डॉलर की लागत आणी। यह करीब 90 हजार वर्ग मीटर में फैला होगा। ट्रंप ने पहले कहा था कि इस बालरूम में 650 लोग बैठ सकेंगे, लेकिन बुधवार को ट्रंप ने कहा कि इसकी क्षमता 999 लोगों की होगी। यह ट्रंप प्रशासन द्वारा किया जाने वाला अभी तक का सबसे बड़ा

पुनर्निर्माण कार्य है। इस बालरूम की खासियत ये होगी कि ये बेहद विशाल होगा, जिसमें राष्ट्रपति का उद्घाटन समारोह भी आयोजित किया जा सके गा। नए बालरूम को बुलेटप्रूफ ग्लास से बनाया जाएगा। नए बालरूम के निर्माण में व्हाइट हाउस के डिजाइन का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस एक खास जगह है और हमें इसका ध्यान रखना होगा। मेन्यू भी रहा खास ट्रंप की इस पार्टी में शामिल हुए लोग बिजनेस सूट और महिलाओं गाउन पहने नजर आईं। सभी मेहमानों के लिए टेबल अरक्षित थीं, जिन पर मोमबत्ती, गुलदस्ते, पानी आदि रखा हुआ था। मेहमानों को सोने की परत चढ़ी प्लेटों में खाना परोसा गया।

भारत से विदा हुआ मानसून, चार महीने में सामान्य से अधिक हुई बारिश; पहाड़ों से लेकर मैदान तक मचाई तबाही

पूरे देश में पहुंचा। 2020 में 26 जून तक पूरे देश में पहुंचने के बाद से यह मानसून



का सबसे जल्दी आगमन था। दरअसल, प्राथमिक वर्षा-वाहक प्रणाली आमतौर पर 1 जून तक केरल में प्रवेश करती है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेती है। यह 17 सितंबर के आसपास उत्तर-पश्चिम भारत

से पीछे हटना शुरू करती है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से विदा हो जाती है। 4 महीने में सामान्य से अधिक बारिश देश में 30 सितंबर को समाप्त हुए पूरे चार महीने के मानसून सीजन में प्रांतिगत कम है। आईएमडी महानिदेशक ने कहा, इस मानसून सीजन में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश 1901 के बाद दूसरी सबसे कम रही। इस क्षेत्र में मानसून सीजन में सबसे कम बारिश (1,065.7 मिमी) 2013 में दर्ज की गई थी। उत्तर-पश्चिम भारत में 747.9 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य 587.6 मिमी से 27.3 प्रतिशत अधिक है। यह 2001 के बाद से सबसे

महापात्र ने कहा कि जून-सितंबर मानसून सीजन में भरपूर बारिश के बाद अक्टूबर में सामान्य से 15 प्रतिशत अधिक बारिश होने की उम्मीद है। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 1,089.9 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य 1,367.3 मिमी से 20 प्रतिशत कम है। आईएमडी महानिदेशक ने कहा, इस मानसून सीजन में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश 1901 के बाद दूसरी सबसे कम रही। इस क्षेत्र में मानसून सीजन में सबसे कम बारिश (1,065.7 मिमी) 2013 में दर्ज की गई थी। उत्तर-पश्चिम भारत में 747.9 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य 587.6 मिमी से 27.3 प्रतिशत अधिक है। यह 2001 के बाद से सबसे

अधिक और 1901 के बाद से छठी सबसे अधिक बारिश थी। महापात्र ने कहा कि उत्तर-पश्चिम भारत के सभी जिलों में जून, अगस्त और सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। पंजाब में बाढ़, पहाड़ों पर भूस्खलन इस बार पंजाब को दशकों में सबसे भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा, जहां उपनती नदियां और टूटी नहरों ने हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को जलमग्न कर दिया और लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। वहीं पहाड़ी राज्यों में बाढ़ फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण भूस्खलन हुआ और बड़े स्तर पर नुकसान हुआ गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पुल और सड़कें बह गईं,

जबकि जम्मू-कश्मीर में बार-बार बाढ़ फटने और भूस्खलन की घटनाएं हुईं। आईएमडी ने इस अतिरिक्त बारिश का श्रेय सक्रिय मानसून को दिया, जिसे लगातार पश्चिमी विक्षोभों का समर्थन मिला था, जिससे क्षेत्र में बारिश में वृद्धि हुई। इधर, मध्य भारत में 1,125.3 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य 978 मिमी से 15. प्रतिशत अधिक है, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीप में सामान्य 716.2 मिमी से 9.9 प्रतिशत अधिक बारिश हुई। भारत में जून में सामान्य से 8.9 प्रतिशत अधिक, जुलाई में 4.8 प्रतिशत अधिक, अगस्त में 5.2 प्रतिशत अधिक और सितंबर में सामान्य से 15.3 प्रतिशत अधिक बारिश हुई।

कोलंबिया की अत्रातो नदी में मरकरी प्रदूषण, मानवाधिकार संकट

आदिवासी समुदाय के लिए बड़ा खतरा

बोगोटा (एजेंसी)। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि कोलंबिया की अत्रातो नदी में अवैध सोने की खान से होने वाला मरकरी प्रदूषण एक गंभीर और चल रहा मानवाधिकार संकट पैदा कर रहा है। यह प्रदूषण उन आदिवासी और अफ्रीकी कृषक समुदायों के जीवन और स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा है, जो नदी पर अपनी खाद्य, जल और सांस्कृतिक जरूरतें निर्भर करते हैं। तीन यूएन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने सार्वजनिक की गई एक पत्र

में कोलंबियाई सरकार पर 2016 में दिए गए सचिवायिक न्यायालय के फैसले को लागू करने में नाकामी पर चिंता जताई। उस



फैसले में अत्रातो नदी को कानूनी पहचान

और संरक्षण का अधिकार दिया गया था। यूएन विशेष रिपोर्टर मारकोस ओरिल्लाना ने कहा दस साल बीत गए हैं, लेकिन उस फैसले के कार्यान्वयन में प्रगति प्रगति नहीं हुई है। बड़ी समस्या संगठित अपराध, पारा और सोने की तस्करी और सुझा बलों में भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। वन्यजीवन और स्थानीय खाद्य स्रोतों को गंभीर नुकसान अत्रातो नदी, कोलंबिया की प्रमुख नदियों में से एक, पश्चिमी एंडीज से कर्बिवियाईपारा तक लगभग 500 मील बहती है। यह चोको

की हरी-भरी और जैव विविधता संपन्न लेकिन गरीब क्षेत्र से होकर गुजरती है, जहां अधिकांश आबादी मछली पकड़ने और छोटें पैमाने पर खेती पर निर्भर है। अवैध सोने की खान अमेजन क्षेत्र में जंगलों की कटौत और प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक है। सोने को बढ़ती कीमत और कमजोर गिरगारी प्रणाली ने अवैध सोने की मांग बढ़ा दी है। पारा, जो सोना निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, अब वन्यजीवन और स्थानीय खाद्य

स्रोतों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। जनसंख्या का बड़ा हिस्सा पारा के संपर्क में ओरिल्लाना ने बताया कि अत्रातो नदी के बेसिन की एक तिहाई आबादी पारा के उच्च स्तर के संपर्क में आ चुकी है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमाओं से अधिक है। पारा अत्यंत विषैले तत्वों में से एक है और यह नसों को नुकसान, अंगों की विफलता और गर्भ में बच्चों के विकास पर प्रतिकूल असर डाल सकता है।